

झारखण्ड देखो

Jharkhand Dekho

खबरें, कहानी, लोग और बहुत कुछ



Digital Edition

www.jharkhanddekho.com

• वर्ष 02 • अंक 16 • पृष्ठ 6 • बुधवार 2 फरवरी 2022

Email - Jharkhanddekho@gmail.com | epaper - Jharkhanddekho.com



UDISE Code- 20110108005, JEPC Code- RTE/20/2021-22
Affiliated By Jharkhand Education Project Council

RGS गुरुकुल
 (An Unit of Shatan Ashram)

Bright Future for your Kids
 For More Detail : www.rsggurukulam.com, Email- gurukulamrgs@gmail.com

Dhadhkia, Dumka, Mob.- 8409399342 (Principal), 7903712653 (Vice Principal)

Opening Shortly IX to X (JMC Board)

Class Nursery to VIII
Medium Hindi & English
Admission Open
 For More Detail : www.rsggurukulam.com

School Men Facility Available








बजट 2022

पीएम आवास योजना के तहत

80 लाख बनेंगे सस्ते घर

टैक्स भरने में यदि हुई गलती, कोई बात नहीं

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि क्लफमें खासियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त दिया जाएगा। साथ ही कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। सरकार ने क्लफमें गड़बड़ी पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान भी किया है। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रावधान किया गया है। टैक्सपेयर किसी भी एसेसमेंट ईयर के अंतिम दिन से

अगले 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी अगर आपने 2022-23 का रिटर्न फाइल किया और उसमें कुछ बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए 2024-25 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा। यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना का ऐलान किया। कर्मचारियों को पेंशन पर भी टैक्स छूट मिलेगी। वहीं, NPS में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा।

नयी दिल्ली/एजेंसी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (डिआ) के तहत 48,000 करोड़ रुपये से 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। ये घर ग्रामीण क्षेत्रों

दोनों स्थानों पर होंगे। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, 'पीएमएवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में चिन्हित पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।' उन्होंने कहा, 'इसमें शहरों और ग्रामीण दोनों इलाके के घर शामिल हैं और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी आवश्यक भूमि और निर्माण संबंधी मंजूरी को लेकर समय कम करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगी, ताकि शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और माध्याम वर्ग के लोगों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा दिया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा, 'हम

मध्यस्थता की लागत में कमी के साथ-साथ पूंजी तक पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ भी काम करेंगे। इससे पहले सोमवार को जारी आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में पीएम आवास योजना के तहत 25 नवंबर तक 33.99 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सिमनेचर ग्लोबल ग्रुप और अध्यक्ष, एसोचैम-नेशनल कार्टिसिल ऑन रियल एस्टेट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रदीप अग्रवाल कहते हैं, 'सरकार ने हमेशा अप्रोडैबल आवास पर ध्यान केंद्रित किया है और इस बजट में, पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन के संबंध में घोषणा की गई, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सरकार ने 2022-23 में अप्रोडैबल श्रेणी में 80 लाख घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। यह समग्र आवास उद्योग के लिए एक प्रमुख बूस्टर हो सकता है। यह सेक्टर में सकारात्मक भावना लाएगा और मांग और आपूर्ति दोनों में वृद्धि करेगा। यह एक संतुलित बजट था जिसने शहरों में बहु-मॉडल परिवहन में सुधार और राजमार्गों को 25000 किमी तक बढ़ाने सहित समग्र आर्थिक विकास का ध्यान रखा। परिवहन में सुधार से शहरों में रोजगार पैदा होगा जिससे और आवास की मांग बढ़ेगी।

- » वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुद्धार आया, आर्थिक वृद्धि 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- » वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत, 2022-23 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- » वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपये अनुमानित, कर्ज के अलावा कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
- » आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं। मानक कटौती भी यथावत।
- » तराशे और पोलिश हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- » अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य, चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य को 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये किया गया।

43 वें झारखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

सर्वपं और बलिष्ठता है हमारी पहचान

आभार

1204.37 करोड़ की लागत से अस्थित इलाके में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु दुमका में अब तक की सबसे बड़ा रानीश्वर-मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए

मसलिया के 204 रानीश्वर के 72 गांव में पहुंचेगा सिंचाई के लिए पानी 22283 हेक्टेयर में उपलब्ध होगी कृषि के लिए सिंचाई

निवेदक : हम सभी दुमका विधानसभा क्षेत्र की जनता

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनें

संतोष सिन्हा
जिला अध्यक्ष
राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), दुमका
मो. : 8210067708

प्रभाकर प्रसाद
अध्यक्ष
राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी
झारखंड प्रदेश

मा. श्री राजा पीटर उर्फ गोपाल कृष्ण पातर
पूर्व मंत्री झारखंड सरकार

झारखंड: कोयला खदान में चाल धंसने से 13 की मौत

धनबाद/एजेंसी।

झारखंड के धनबाद जिले में कोयले की खदान में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कोयला खदान में उतरे मजदूर चालकर गिरने से दब गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 13 मजदूरों की मौत हुई है। अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर है। हालांकि, पुलिस अभी भी इस मामले में कुछ भी बोलने से पीछे हट रही है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, खदान में अवैध खनन किया जा रहा था। इसी दौरान एक कोयले से भरा चालकर 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। इसकी चपेट में कई मजदूर आ गए, जिसमें 13 लोगों की मौत पर ही मौत हो गई। आनन-फानन में कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि खदान में अभी भी राहत कार्य जारी है। कई लोग नीचे दबे हुए हैं।



!! HURRY !!

मित्र सेवा के साथ बनें बैंक मित्र और बैंक मित्र बनकर करें

Aeps, DMT, MATM, Bill Payment और Recharge

साथ ही हर ट्रांसक्शन पर कमाएं

अधिक कमीशन

अधिक जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए सम्पर्क करें :

9151005283
9006469840

एक बार भुगतान आजीवन व्यापार

Mitr Sewa
With Sabko Dimaar



Immediately Required
Franchise / Mitr Sewak
for working on following services on commission basis:-

- Amazon Easy store
- Mitr Digi Portal (AEPS, , DMT, ATM, RECHARGE, BILL PAYMENTS etc.)
- Online Bima for all major Bima Companies
- Online E-Store for E-Commerce
- Mutual fund, Tax filling, NPS, Share, Demat / online Trading
- Other services

Registration Charges
2000+GST

Income opportunity of
Rs. 40,000-60,000 with les investment

Immediately contact

Shri : Manoj Kumar
Post : Area Manager, Mitr Sewa Foundations
Mob : 9151005283, 9006469840
Email : manoj.kumar@mitrsewa.in

संक्षिप्त समाचार

दुमका में ग्रामीण विकास विभाग के क्लर्क की हत्या, सड़क पर मिला शव



दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत दीप कुमार श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई है। वह विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। घटना नगर थाना के शिव मंदिर रोड की है। दीप का शव जिस घर में रहते थे उसी के सामने सड़क के किनारे मंगलवार को मिला है। उसके सर और चेहरे पर काफी खून बिखरा हुआ है। दुमका नगर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार मौके पर पहुंच गए हैं और जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दीप कुमार 2 साल से दुमका में कार्यरत थे। वह मूल रूप से रांची के रातू रोड के रहने वाले थे। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ विशेष कहा जा सकता है। मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है कि कल शाम से वो किनके संपर्क में थे।

1978 से दिशोम गुरु शिवू सोरेन के नेतृत्व में मनाया जाता है दो फरवरी को पार्टी का स्थापना दिवस : नलिन सोरेन



दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बुधवार को 43 वां झारखण्ड दिवस मनाया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण दुसरी दफा कार्यक्रम दिन में 12 बजे से 2 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झामुमो सुप्रियो शिवू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दुमका के विधायक बसंत सोरेन, जामा विधायक सीता सोरेन एवं शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन मौजूद रहेंगे। शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन ने बताया कि 1978 से दिशोम गुरु शिवू सोरेन के नेतृत्व में प्रति वर्ष दो फरवरी को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम मुख्यतः शाम 5 बजे शुरू होता है जो लगभग रात भर चलता है। पूरे संध्याल परगना से हजारों की संख्या में लोग दिशोम गुरु शिवू सोरेन को सुनने पहुंचते हैं। पिछले वर्ष से कोरोना के कारण कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर दिन में किया जा रहा है। बुधवार को भी 12 बजे से 2 बजे तक दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झारखण्ड दिवस का आयोजन किया गया है।

डॉ प्रभात रंजन को दिया गया डीएस का प्रभार

देवघर/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ प्रभात रंजन को डीएस का पदभार दिया गया है। अब वे बतौर डीएस कार्यभार संभालेंगे। बताया कि पूर्व डीएस डॉक्टर नन्दलाल पंडित 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं। वहीं डीएस कार्यालय ने पत्र जारी कर बताया गया है कि डॉक्टर नन्दलाल पंडित चिकित्सा पदाधिकारी सह प्रभारी उपाध्यक्ष कि सेवानिवृत्ति को देखते हुए सदर अस्पताल देवघर में कार्यों की समुचित रूप से निर्वहन हेतु कार्य व्यवस्था के तहत डॉ प्रभात रंजन चिकित्सा पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से आने आदेश तक सदर अस्पताल देवघर के प्रभारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। डॉक्टर नन्दलाल पंडित समस्त धारित प्रभार डॉ प्रभात रंजन चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपेंगे।

दुमका पहुंचे मुख्यमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर



झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को दुमका पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं राज्यसभा सांसद शिवू सोरेन का दुमका हवाई अड्डा में आयुक्त तथा जिला प्रशासन द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, एसडीपीओ समेत जिले के तमाम अधिकारी उपस्थित थे।

आमजनों की समस्याओं को दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री



झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। खिजुरिया स्थित आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आमजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। बड़ी संख्या में लोग आवेदन के साथ मुख्यमंत्री से मिलने आये थे। सभी ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत

कराया। समस्याओं ने निष्पादन हेतु उन्होंने संबंधित को निदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपकी सरकार है। आपकी समस्याओं को दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से योग्य लाभुकों को योजना लाभ देने का कार्य कर रही है। सरकार

की सभी कल्याणकारी योजनाएं यहाँ के लोगों को ध्यान में रख कर बनायी जा रही है। समाज के अतिम योग्य व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले इस उद्देश्य के साथ सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। इस दौरान विधायक महेशपुर स्टीफन मरांडी, विधायक बसंत सोरेन भी उपस्थित थे।

मसलिया के कई गांवों को जोड़ने वाली दो मुख्य सड़क व ब्लॉक क्वार्टर भवन निर्माण कार्य को विधायक ने कराया शुरुआत

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। विधायक सह झामुमो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत सोरेन ने दुमकवासियों के लिए सौभाग्य की पिटारा खोलते हुए कई योजनाओं का विधिवत रूप से भूमि पूजन कर कार्य का शुरुआत कराया। विधायक श्री सोरेन ने प्रखंड क्षेत्र के सितासाल से राजमहल तक करीब पांच किलोमीटर सड़क जो काफी दिनों से जर्जर था, राहगीरों को सड़क से साईकल तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल होती थी।



सड़क बनाने की मांग अरसे से ग्रामीणों की थी। ग्रामीणों की मांग को विधायक ने पूरा करवाते

महिला पर्यवेक्षिका उषा कुमारी की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। बाल विकास परियोजना कार्यालय दुमका में महिला पर्यवेक्षिका के पद पर कार्यरत उषा कुमारी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दुमका रीता बेसरा ने महिला पर्यवेक्षिका उषा कुमारी को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया और कहा कि उषा जी बहुत ही योग्य कर्मठ और अनुशासित सुपरवाइजर रही हैं। अपने



महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमारे विभाग में उषा जी हमेशा हमलोंगों याद आयेंगी। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश

सिन्हा और अंचल अधिकारी यामुन रविदास ने भी अपने विचार व्यक्त किए गए और उषा कुमारी को बहुत ही व्यवहार कुशल बताया।

उन्के कार्य कलापों की सराहना की और साथ ही यह भी कहा कि महिला पर्यवेक्षिका उषा से अन्य कर्मियों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। कार्यक्रम में दुमका प्रखंड के प्रमुख हेमंत हेम्ब्रम सहित संबंधित कार्यालय परिवार के सभी कर्मी एवं महिला पर्यवेक्षिका मीना साह, सरोजिनी सोरेन, दिपाली मिश्रा, मुखी मुर्मू, टेरेसा मराण्डी, प्रखण्ड समन्वयक सुजाता कर्ण, तेजस्विनी के संदीप वर्मा, रोहित कुमार, मोनिका किस्कू और विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों से आई सेविका सहायिका उपस्थित थी।

कोविड-19 के तहत होगा स्थापना दिवस का आयोजन-बसंत सोरेन



दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। झामुमो के 43 वें झारखंड दिवस में भाग लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं झामुमो सुप्रियो सह पूर्व मुख्यमंत्री शिवू सोरेन दुमका पहुंचे चुके हैं। ज्ञात हो कि दो फरवरी को दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 43 वां झारखंड मनाया जाएगा। दो फरवरी का दिन झामुमो के लिए खास है, इस दिन का विशेष महत्व है। दो फरवरी को दिशोम गुरु झामुमो का ध्वज फहराकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं तत्पश्चात पार्टी की नीतियों से आमजनों को अवगत कराया जाता है। इस बार जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, सिर्फ दुमका जिले के विधायक ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिले के विभिन्न प्रखंडों से सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसकी जानकारी दुमका विधायक बसंत सोरेन ने प्रेस वार्ता कर दिया। बिहारी ने कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन के तहत स्थापना दिवस मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन एवं पार्टी के केन्द्रीय महासचिव विजय कुमार, अब्दुल सलाम, आलोक सोरेन आदि मौजूद थे।

नोनीहाट में सड़क हादसे में खलासी की मौत

दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। नोनीहाट-दुमका मुख्य पथ पर नोनीहाट बस स्टैंड के पास सोमवार की रात 11 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने युवक की मौत हो गई। युवक का सिर कुचल गया था। मृतक की पहचान शारंगपानी गांव के पंचू लायक (29) के रूप में हुई। वह नोनीहाट के टुक में खलासी था। हंसडीहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए फूलो ज्ञानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया।

दुमका के वकीलों ने काला बिल्ला लगाया

दुमका/झारखंड देखो/प्रतिनिधि। झारखंड हाईकोर्ट के वकील हेमंत सिकरवार पर हजारीबाग में जानलेवा हमले की घटना से वकीलों में रोष है। मंगलवार को दुमका जिला बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखा। वकील न्यायिक प्रक्रिया से दूर रहे। दुमका के वकीलों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। दुमका जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने घटना की निंदा की।

आम जनता के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा केन्द्रीय बजट : सुनील सोरेन

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। सांसद सुनील सोरेन ने भारत सरकार के द्वारा मंगलवार को पेश किए गए बजट की सराहना की है। सुनील सोरेन का कहना है कि यह बजट सिर्फ 1 या 2 वर्ष के लिए रोडमैप तैयार नहीं करेगा बल्कि अगले 25 साल के ग्रोथ लिए ब्लूप्रिंट तैयार होगा। इस बजट से देश के विकास को बल मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए नौकरियों का अवसर प्राप्त होगा। सांसद ने कहा कि आज देश में युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत नौकरियों की है ऐसे में आज के बजट में जो 16 लाख लोगों को सरकार ने नौकरी देने की का वादा किया है, यह काफी सराहनीय है। इसके साथ ही 80 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। जिसमें सरकार ने 48 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है। यह गरीबों के लिए काफी राहत की खबर है। दुमका सांसद ने कहा कि आगामी 3 साल में 400 बंदे भारत ट्रेन बनाने की जिस योजना सरकार ने घोषणा की है इससे सीधे तौर पर आम लोगों को लाभ पहुंचेगा। सांसद ने केन्द्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के विकास का भी ध्यान रखा है और यह घोषणा की है कि राज्यों को मुफ्त ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा हुई। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 15 सौ करोड़ रुपए के पैकेज देने की भी बात



बजट में कही गई है। सांसद ने कहा कि आज पूरे देश में हाईवे का जाल बिछाई जा रही है और आज के बजट में इसमें 25 हजार किलोमीटर हाईवे बनाने की घोषणा हुई है जो कि देश के विकास में सहायक साबित होगा। कुल मिलाकर यह कहे कि आज का बजट आम जनता का तो बजट है ही साथ ही साथ पूरे देश को तीव्र गति से विकसित करने वाला बजट है।

गरीब किसान विरोधी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला है आम बजट: अमरेन्द्र यादव

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

दुमका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि वित्त मंत्री ने आम बजट को 25 सालों का दूरदर्शी बजट बताकर देश के बेरोजगार युवाओं को छलने का काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था को तत्कालिक सुधारने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। बजट में मध्यमवर्गीय लोगों के लिए टैक्स स्लैब में कोई रियायत नहीं दिया गया है, जबकि सरकार के पूंजीपति मालिकों के लिए कारपोरेट टैक्स में रियायत दिया गया है। देखा जाए तो यह जनता की उम्मीदों पर पानी फेंकने वाला बजट है। वित्त मंत्री ने आंकड़ेबाजी कर आम जनता को गुमराह किया है। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। युवाओं को भी निराशा हाथ लगी



है। पूर्व में की गई रोजगार की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुईं। पुनः नए नौकरी का वादा किया जा रहा है। लेकिन यह नौकरी किस क्षेत्र में दिया जाएगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। किसानों को इस बार भी बजट से निराशा हाथ लगी है। क्योंकि उनकी आय दोगुनी करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जिससे यह भी जुमला साबित हुआ है। देश का गरीब तबका बढ़ती महंगाई से परेशान है। लेकिन इसमें महंगाई निर्वन्त्रण की दिशा में कोई घोषणा नहीं करते हुए उल्टे महंगाई बढ़ाने का काम किया है। किसानों के लिए फर्टिलाइजर में मिलने वाली सब्सिडी की

राशि 40 हजार करोड़ घटा दिया गया है। फूड सब्सिडी में भी 80 हजार करोड़ कटौती की गई है। पेट्रोलियम उत्पादों पर एक हजार करोड़ की सब्सिडी कम कर दी गई है। किसानों को कर्जा माफ़े की बात तो दूर उन को भ्रमित करने के लिए ड्रोन पर सब्सिडी की बात कही गई है। जिसका हमारे देश के ज्यादातर किसानों के पास कोई उपयोग नहीं है। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में भी बजट कम कर दिया गया है। इससे यह साबित होता है कि यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला, उद्योगपतियों की जेब भरने वाला, आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला बजट साबित होगा। पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने कहा था आप मुझे 10 वर्ष का मौका दें मैं देश की तकदीर को बदल दूंगा। अब सरकार को 25 साल का मौका चाहिए। यह बिबुलुल हास्यास्पद प्रतीत होता है।

संक्षिप्त समाचार

अपने दो बच्चों की वापसी हेतु पुलिस से लगाई गुहार

गिरिडीह। एक पिता ने अपने दो बच्चों के सकुशल वापसी के लिए पुलिस से गुहार लगायी है। तिसरी निवासी भादो मरांडी ने अगल अलग गांव के तीन लोगों पर मानव तस्करी का आरोप लगाते हुआ मामला दर्ज कराया है। मामला गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र का है।

महिला थाना को दिए आवेदन में पीड़ित व्यक्ति ने कहा है कि तिसरी के ही रहने वाले मनोज हांसदा, सावना सोरेन और सुनील यादव ने उनके बच्चों को काम दिलाने का प्रलोभन देकर दिल्ली ले जाने की बात कही थी। इसके लिए उन लोगों ने 26 हजार रुपये भी दिये थे। उनकी बात में आकर उसने 15 वर्षीय बेटा सुनील मरांडी और 12 वर्षीय बेटा अरविंद मरांडी को उनके साथ भेज दिया। लेकिन अब उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसने अपने आवेदन में कहा कि बीते महीने जनवरी में जब वह अपने बच्चों से फोन पर बात कर रहा था, तो दोनों काफी डरे हुए थे, वे लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, इसकी जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद उसने सावना सोरेन से दोनों बच्चों को वापस लाने को कहा तो वह टालमटोल करता रहा। भादो मरांडी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही सावना ने उसके भाई के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट किया कि तीनों के खिलाफ कोई केस दर्ज न कराया जाए। अब जबकि उसके दोनों बच्चे मुश्किल में हैं तो वो अपने दोनों बच्चों को सकुशल वापस चाहता है।

एसीबी ने बिजली कर्मी को 2 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

धनबाद। धनबाद में एसीबी ने आज मंगलवार को सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कर्मी को दो हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। बताया जाता है कि धनबाद में पदस्थापित विद्युत अवर प्रमंडल धनबाद के बड़ा बाबू शिवकुमार मथी ने करकेंद्र डिवीजन के जूनियर लाईनमैन मरांडी से इंफॉर्मेट पास कराने के एवज में पांच हजार रुपये की मांग रखी थी। जिसके बाद जूनियर लाइन ने मामले की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय को सूचना दिया जिसकी तहकीकात करने के बाद मामला सत्य पाए जाने पर एसीबी ने टीम गठित कर विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय में घेराबंदी की जहां जूनियर लाईनमैन को पांच हजार रुपये की मांग के एवज में दो हजार रुपये का भुगतान किया जिसके बाद एसीबी ने मौके पर पैसे के साथ बड़ा बाबू को रंगे हाथ पकड़ा। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद एसीबी की टीम ने उसे अपने कार्यालय ले गई। जहां उससे पूछताछ चल रही है। इस बाबत एसीबी के पदाधिकारियों ने बताया कि विभाग का वर्ष 2022 का यह पहला मामला है, जिसमें रिश्वत लेते सरकारी कर्मी को पकड़ा गया है।

प्लस टू उच्च विद्यालय बड़कागांव को मॉडल स्कूल बनाने के लिए सर्वेक्षण



बड़कागांव। बड़कागांव प्लस टू उच्च विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने के लिए क्लिफ्टर कन्सेल्टेंट रॉची की टीम के द्वारा सर्वेक्षण किया गया। टीम ने पूरे विद्यालय परिसर को सर्वेक्षण कर विद्यालय परिवार से पूरी जानकारी ली। मॉडल स्कूल बनाने के लिए आवश्यकतानुसार नए भवन निर्माण के साथ-साथ जर्जर भवनों का मरम्मत, लैब, लाइब्रेरी खेल मैदान, खेल सामग्री, शौचालय का निर्माण, पानी की व्यवस्था से लेकर सभी तरह की आधुनिकता व्यवस्था करने का प्रावधान है। सर्वेक्षण टीम में रॉची रहान से मुकुंद रंजन, हजारीबाग जिला अभियंता सीबी सिंह, कनीय अभियंता संजय कुमार ठाकुर, शामिल थे। टीम द्वारा विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सुधा कुमारी एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह से पूरी जानकारी ली। इस अवसर पर शिक्षक मनीष चंद्र पांडे, कुलेश्वर महतो, दीपक प्रकाश, अशोक राम, निकास रजवार, अमित शर्मा, जितेंद्र कुमार, युवराज सिंह, पारसनाथ महतो सहित अन्य लोग सर्वेक्षण टीम को सहयोग कर रहे थे।

पूर्व कोडरमा सांसद पर हमला के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

तिसरी/गिरिडीह। कोडरमा लोक सभा क्षेत्र के पूर्व सांसद रविन्द्र कुमार राय पर जानलेवा हमला होने के विरोध में मंगलवार को तिसरी प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ता

आक्रोशित होकर तिसरी मुख्यालय स्थित गांधी मैदान से तिसरी पैदल मार्च निकाल नारे बाजी करते हुए तिसरी चौक पहुंच कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर हमला में सामिल अपराधियों की अभिलंब गिरफ्तारी करने का मांग

किया गया। हेमंत सरकार हाथ हाथ, गद्दी छोड़ो, विधि व्यवस्था दुरुस्त करो समेत कई नारा लगाया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा राज्य में आम तो आम खास लोग भी सुरक्षित

नहीं है। जज से लेकर वरिष्ठ नेता अधिकारी पर हमला हो रही है पुलिस व खुफिया तंत्र फेल हो गई है हेमंत सरकार के शासन में नक्सली, अपराध, भ्रष्टाचार में काफी बढ़ोतरी हुई है हेमंत सोरेन सरकार चलाने में सक्षम नहीं है।

उन्हे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कार्यकर्ता लक्ष्मण मोदी, चंदेरी मंडल अध्यक्ष रवींद्र पांडित, अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रकाश पासवान, तिसरी थाना सांसद प्रतिनिधि सुनील साव

, भाजपा किसान मोर्चा तिसरी मंडल अध्यक्ष कपिल यादव, तिसरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, सोदागर पंडित, बालमुकुंद राम, उपेंद्र साव, बिरेंद्र राय, संदीप शर्मा, अर्जुन यादव, जानकी यादव, कृष्णा सिन्हा समेत दर्जनों लोग शामिल रहे।

यादव समाज का वनभोज कार्यक्रम सम्पन्न, यादव भवन निर्माण का लिया गया निर्णय



झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

गिरिडीह। तिसरी प्रखंड के कलवा नदी के किनारे यादव समाज का वनभोज सह मिलन कार्यक्रम राष्ट्रीय यादव सेना के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। वनभोज कार्यक्रम में प्रखंड के सभी पंचायत के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय यादव एवं संचालन सेना के प्रखंड अध्यक्ष लालू यादव ने किया। बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का हर सम्भव प्रयास करने का निर्णय लिया गया। निर्णय लिया गया कि तिसरी प्रखंड मुख्यालय में यादव भवन सह छात्रावास का

निर्माण किया जाएगा जिससे समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल लाया जा सके। वहीं सभी पंचायतों में बैठक कर सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहु छोड़छाड़, जमीन विवाद आदि को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य रामकुमार राउत, कृष्ण मिशन सोसाइटी के संस्थापक डॉ अशोक यादव, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, जिन सदस्य प्रतिनिधि किमुन यादव, राष्ट्रीय यादव सेना के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील यादव, महासभा के रामचंद्र यादव, सत्यनारायण



यादव, नंदकिशोर यादव, विनोद यादव, मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव, सुरेश यादव, जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप यादव, वकील श्याम सुंदर यादव, सेना के प्रखंड उपाध्यक्ष प्रकाश यादव, सोनू यादव, सचिव अशोक यादव, विजय यादव, युवा अध्यक्ष उदय यादव, रामचरित्र यादव, रवि यादव, भूषण यादव, कपिल यादव, अनिल यादव, मदन यादव, छोटी यादव, कैलाश यादव, दिनेश यादव, बाबूलाल यादव, प्रमोद यादव, अजय यादव, शशि यादव, सुनील यादव, शक्ति यादव, विनोद यादव, लखन यादव, किशोरी यादव, नागेश्वर यादव, महेश राउत, कोषाध्यक्ष आलोक यादव,

निदेश यादव, जानकी यादव, मनु यादव, दामोदर यादव, मुकेश यादव, पप्पू यादव, पवन यादव, तारकेश्वर यादव, अजित यादव, मंटू यादव, लाटो यादव, अशोक यादव, उपेंद्र यादव, पिन्टू यादव, डॉ सतेंद्र यादव, गोकुल यादव, योगेंद्र यादव, कैलाश यादव, दशरथ यादव, दिनेश यादव, भुखन यादव, मुकेश यादव, सदानंद यादव, कोंग्रेस यादव, उमेश यादव, शिवकुमार यादव, महेश यादव, विकास यादव, लातो यादव, कमल महतो, मनोज यादव, राकेश यादव, भीखन यादव, मोहन यादव, कमलेश यादव, गोपाल यादव, चंदन यादव, लक्ष्मी नारायण यादव आदि मौजूद थे।

माकपा माले निमाडीह लोकल कमिटी की बैठक हुआ संपन्न

गांवा में मनरेगा और योजनाओं में स्वीकृति के नाम पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का नंगा नाच हो रहा है : राजकुमार यादव

झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

गिरिडीह। गांवा प्रखंड अंतर्गत निमाडीह पंचायत के ग्राम विस्नीटिकर में भाकपा माले लोकल कमिटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकपा माले प्रखंड कमिटी सदस्य प्रदिप यादव एवं संचालन रंजीत कुमार ने किया इस बैठक में पार्टी मजबूती, नए सदस्यों की भर्ती, रेनुवल एवं ब्रंचो की पुनर्गठन को लेकर रणनीति बनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा की अभी लगतार ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आए दिन मनरेगा योजना हो या कोई अन्य काम बिना पैसा के स्वीकृति नहीं करते है। यदि नौजवानों को मनरेगा में स्वीकृति नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। दुसरी ओर जिस तरह कोरोना के कारण जिस तरह से पलायन है बेरोजगारी है तो सरकार की ऐ ज़िम्मेवारी है मनरेगा ऐक्ट को मजबूती से लागू किया जाए। और उन्हेने



कहा की आज मोदी सरकार द्वारा किसानों के साथ गद्दारी किया और जो समझौता हुआ उसे लागू नहीं किया गया। नौजवानों के आर आर बी और एन टी पीसीके रिजल्ट में धांधली हुवा और छात्रों द्वारा सरकार से रेलवे और एनटीपीसी रिजल्ट जांच की मांग की किया गया तो छात्रों के उपर बर्बता तरीके से लाठी बरसाया गया इसकी हम कड़ी निंदा करते

हैं हम हेमंत सरकार से मांग करते हैं की झारखण्ड में 1932 की स्थानीय नीति लागू करे और युवाओं को स्थानीय पहल पर बहाल करे। मौके पर रंजीत कुमार, प्रदीप कुमार, पंकज यादव, संतोष पांडित, भोला यादव, अनिल कुमार, बबलू यादव, विकास यादव, मोहन यादव, रमेश कुमार समेत दर्जनों नौजवान शामिल रहे।

अधिवक्ताओं ने इंडसाफ के लिए किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन



झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

गिरिडीह। बार एसोसिएशन गिरिडीह के सामने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एकदिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। धरना का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ता पर हो रहे आक्रमण अधिवक्ताओं के साथ दूर व्यवहार को लेकर यह धारणा दिया गया था। धरने में सभी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बड़े दुख के साथ भाग लिया और आज का दिन पेन डाउन रखा गया।

धरना प्रदर्शन के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई कि प्रशासन को या समाज को अधिवक्ता जो समाज में न्याय दिलाने के लिए हमारे पास है। उनके साथ दुर्व्यवहार उनके उपर आक्रमण एक निंदनीय कार्य है। जिसको अधिवक्ता परिवार, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन किसी भी किसी किमत पर बरदाश्त नहीं करेगा। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से गिरिडीह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाश सहाय और बार एसोसिएशन के महासचिव



संचालन भी शामिल रहे। धरना का संचालन अधिवक्ता साजिद मोहम्मद द्वारा किया गया। महासचिव चुन्नु कांत ने कहा की एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को जल्द एक्ट बांकर उसे तुरंत एक्ट की शक्ति में देख कर इस्तेमाल परित किया जाए। और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम में ऐसा प्रचार किया जाए की कोई भी व्यक्ति अधिकारी से दुर्व्यवहार करता है उसे खिलाफ गैर जमानती अपराध माना जाए और उसे 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल दिया जाए।

और उसके लिए किसी भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिवक्ता मंटू सिन्हा, महिला अधिवक्ताओं में उर्मिला शर्मा, कला सहाय, सुनीता सिंह, अन्य अधिवक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। इसके अलावा मुख्य रूप से अधिवक्ता बाल गोविंद साहू बबन, अधिवक्ता मित्रा, अमित कुमार सिन्हा, बलराम, केपी यादव, फैयाज अहमद, शिवाजी सिंह, अंजनी सिन्हा, सालिनी सिन्हा, एकलव्य, पुरुषोत्तम, उदय सिन्हा, संजीत आदि उपस्थित रहे।

झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज युवाओं ने किया जोरदार स्वागत



झारखंड देखो/प्रतिनिधि।

गिरिडीह। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज के प्रथम आगमन पर गिरिडीह युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मो हसनैन अली के नेतृत्व में गिरिडीह युवा की टीम ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। गिरिडीह

युवा कांग्रेस की टीम प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज का ऐतिहासिक काफिला के साथ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से झारखंड कांग्रेस भवन तक पहुंचा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज को हजारां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और रांची के युवाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए बधाई दी। गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष



मो हसनैन अली ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष से गिरिडीह आने का निमंत्रण दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हसनैन अली ने बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी बे-हद ऊर्जावान है और बहुत ही जल्द उनका गिरिडीह आगमन होगा। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों युवा एक साथ युवा कांग्रेस का दामन धारणगे।

मौके पर जिला उपाध्यक्ष शशि शर्मा, गाडेय विधानसभा अध्यक्ष हसनैन आलम, गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष मो सहनवाज, डुमरी विधानसभा अध्यक्ष गंगाधर। जमुआ विधानसभा अध्यक्ष अहमद रजा नूरी। बगोदर विधानसभा अध्यक्ष आबिद अंसारी, युवा कांग्रेस के बेलाल अहमद हसनैन सहित युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

2022
बजटआम लोगों के हाथ कुछ नहीं आया,
पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा ये बजटमंगलवार
एक फरवरी 2022

को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो सबको उम्मीद थी कि लगातार दो सालों से कोरोना की मार, बढ़ती महंगाई, युवाओं में रोजगार को लेकर बढ़ता रोष, कॉरपोरेट्स के निवेश में गिरावट को सरकार इस बजट के जरिए साधने की कोशिश करेगी। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का भी बजट पर असर होगा।

वित्त

मंत्री द्वारा किए गए कुछ ऐलान का तो जरूर दूरगामी असर देखने को मिलेगा। लेकिन आम लोगों की आंकाक्षाएं धूमिल हो गई हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का जिक्र नहीं किया लेकिन उन्होंने अगले 25 सालों में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा उस काल में देश के नवनिर्माण करने की बात कही और उसे अमृतकाल बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में पूंजीगत खर्चों जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं उसमें जबरदस्त

बढ़ोतरी का ऐलान किया। कोरोना महामारी के बीच 2022-23 में सरकार 7.5 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च करेगी जिसके भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सके और विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 25000 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण किया जाएगा। गांवों में सड़क निर्माण पर जोर दिया जाएगा, शहरों में मासट्रांजिट सिस्टम के साथ 3 सालों में 400 नए चंदेभारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।

मोदी सरकार ने हर घर को नल से जोड़ने के लिए भारी भरकम 60,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी जिससे 318 करोड़ घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाया जा सके। सोलर माइड्यूल्स में लोकल मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 19500 करोड़ रुपये का पीएलआई स्कीम लेकर आएगी। इसका बड़ा फायदा घरेलू मैनुफैक्चरिंग को मिलेगा। सरकार ने कम आय वाले लोगों को लिए और ज्यादा घर बनाने का ऐलान किया है। इसका

फायदा रियल एस्टेट से लेकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 2022 में 5जी स्पेक्ट्रम की निलामी होगी। जाहिर है इससे टेलीकॉम सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। सेक्टर में निवेश आएगा। बजट में डाटा स्टोरेज को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से भी कंपनियों को फायदा होगा। डिफेंस सेक्टर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में 68 फीसदी हिस्सेदारी लोकल कंपनियों की होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।

इमरजेंसी क्रेडिट लिंकड स्कीम के तहत छोटी कंपनियों को कर्ज देने की समयसीमा को मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया है और इस योजना के तहत राशि 5 लाख करोड़ रुपये हो गई है। एक अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच बने स्टार्टअप को टैक्स होलिडे का लाभ अब 31 मार्च 2023 तक मिलेगा। कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्कूल बच्चे प्रभावित हुए हैं। बच्चों को डिजिटली पढ़ाई करने के लिए सरकार PM e-Vidya योजना लेकर आ रही है जिसमें हर कक्षा के लिए टीवी चैनल होगा वो भी हर भाषा में। इसके

अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोला जाएगा। वित्त मंत्री क्रिप्टोकॉरेसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगा दिया है। हालांकि क्रिप्टो को लेकर उन्होंने नहीं बताया कि सरकार विधेयक कब तक लेकर आ रही है। निर्मला सीतारमण के बजट से सबसे ज्यादा निराशा मध्यम वर्ग को हुआ है जो पिछले कई महीनों में महंगाई से जूझ रहा है। वेतनभोगियों के हाथों में भी निराशा हाथ लगी है। सरकार से कई टैक्स के जानकारों ने टैक्स में सुधार करने की सुझाव दिया था। टैक्सपेयर्स को उम्मीद थी कि उन्होंने कुछ राहत मिलेगी।

डिमांड और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे देने का भी सुझाव दिया गया था। लेकिन इस बजट में वित्त मंत्री इन लोकलुभावन कदम से बचती नजर आई। वित्त मंत्री का फोकस कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर था। ये भी संभव है कि सरकार ने कुछ घोषणाओं को अगले बजट के लिए छोड़ दिया है क्योंकि 2024 अभी दो साल दूर है।

दूरदराज और गांव-गांव तक
पहुंचेगा ब्रॉडबैंड- सीतारमण

वित्त मंत्री ने अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट मंगलवार को पेश किया है। 2022-23 बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 5G ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की सेवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है।



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट मंगलवार को पेश किया है। 2022-23 बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 5जीऑफ ऑप्टिकल फाइबर की सेवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 में 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। इसके बाद दूरसंचार की निजी कंपनियां देश में 5जी सेवाओं की शुरूआत कर सकेंगी। 5जी सर्विस शुरू होने से स्मार्टफोन को और बेहतर ढंग से यूजर यूज कर सकते हैं।

2025 तक देश के सभी गांव में ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के ऐलान किया कि साल 2025 में देश के सभी गांव में ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से ठेके दिए जाएंगे।

ऑप्टिकल फाइबर के पहुंचने से गांव में और दूरदराज के इलाकों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं के लिए रिचार्ज और डेवलपमेंट में भी बढ़ावा मिलेगा। देश में हर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य भारत सरकार ने भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से करेगी।

इन कंपनियों को 5जी सर्विस शुरू करने की मिलेगी जिम्मेदारी

भारत में जल्द से जल्द 5जी सर्विस शुरू करने के लिए टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया, रिलायंस जियो और एयरटेल कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बेहतर सर्विस व कम दामों में ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा पहुंचाने के लिए इन कंपनियों को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिवेशन फण्ड का 5% भी दिया जाएगा।

तीन चरणों में पूरी होगी परियोजना

पहले चरण में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाकर एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

दूसरे चरण में भूमिगत फाइबर, बिजली लाइनों पर फाइबर, रेडियो और सेटलाइट मीडिया की मदद से देश के सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तीसरे चरण में एक अत्याधुनिक, प्यूर-पुफ नेटवर्क के तहत जिलों और ब्लॉकों के बीच फाइबर को विस्तारित करने हेतु रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।

दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मिलेगा लाभ

ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा शुरू होने से भारत डिजिटल की दुनिया में एक और कदम रख लेगा। इस सेवा के शुरू होने से ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में ग्रामीण बेहतर निर्यात के साथ इंटरनेट सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। ग्रामीण इलाके के लोग इंटरनेट के माध्यम से खेती के लिए और अच्छी तकनीकों की जानकारी ले सकेंगे। जिससे ग्रामीण इलाके के किसानों के कृषि संचार में तेजी आएगी।

क्या महंगा क्या सस्ता?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया। बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गईं। लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, आइए जानते हैं कि क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता...

■ महंगा होगा बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल
■ सस्ते होंगे मोबाइल फोन के चार्जर
■ महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने
■ बारिश से बचाने वाली छतरियां महंगी

महंगा होगा बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के आखिर में घोषणा की कि एक अक्टूबर 2022 से देश में बिना इथेनॉल मिक्स वाले ईंधन पर 2 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगेगा। इसके पीछे सरकार ने ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने का तर्क दिया है। ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद से देश में बिना ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल महंगा हो जाएगा।

सस्ते होंगे फोन के चार्जर
बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की है।

महंगे होंगे हेडफोन, इयरफोन
सरकार ने बजट में Wearable और Hearable के घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी का एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही है। इससे चीन और विदेशों से आयात होने वाले हेडफोन, इयरफोन महंगे होंगे।

सस्ते होंगे रत्न-आभूषण
रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्न पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया है। सिंपली सोन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।

महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने
सरकार ने बजट में अंडरवैल्यू आर्टिफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। ऐसे में आने वाले वक्त में ये गहने महंगे हो सकते हैं।

महंगी होंगी छतरियां
बारिश में भीगने से बचाने वाली छतरियां अब से महंगी हो जाएंगी। सरकार ने बजट में इन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20% कर दिया है। इससे विदेश से आने वाले छतरे महंगे होंगे। साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुत्रों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है।

स्टील कबाड़ का आयात रहेगा सस्ता
छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप (कबाड़) पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इससे टैटए सेक्टर में कबाड़ उत्पाद बनाने वालों को आसानी होगी।

मेथेनॉल हुआ सस्ता
सरकार ने मेथेनॉल पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। इसी के साथ पेट्रोलियम को रिफाइन करने वाले रसायनों पर भी शुल्क कम किया गया है। इससे घरेलू स्तर पर इन क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन का लाभ होगा।

ये भी हुआ महंगा सीमाशुल्क की दरों में बदलाव के चलते कई और वस्तुओं के दाम बढ़ें हैं। इनमें सिंगल या मल्टीपल लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर माइड्यूल, एक्सरे मशीन इत्यादि शामिल हैं। सरकार ने देश में इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम जैसी योजनाएं पेश की हैं, इसलिए इन पर सीमाशुल्क बढ़ाया गया है।

डिजिटल करेंसी से क्या फायदा होगा

केशलेस इकोनॉमी केश पर डिजिटल करेंसी का इद तक कज हो जाएगी	सेटलमेंट तेज होगा डिजिटल करेंसी से ट्रांजेक्शन जल्दी पूरे होंगे	कॉस्ट इफेक्टिव करेंसी नोट्स छापाये और ट्रांजपोर्टेशन का खर्च बचेगा
अध्याचार करेंसी की ट्रेकिंग होगी, जिससे उसे छिपाया नहीं जा सकेगा	टेटर फंडिंग किप्टोकॉरेसी पर लगाए लगेगी तो ट्रेटर फंडिंग को जड़ जिलेगी	

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2022-23 से आम जनता को बड़ी उम्मीदें थीं। माना जा रहा था कि सरकार पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट में कई लुभावनी घोषणाएं कर सकती है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि आम आदमी की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं, यह बेहद अहम है। इकोनॉमिस्ट स्वामीनाथन अख्यर ने इसे महंगाई बढ़ाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि जनता को लुभाने की बजाय सरकार रिस्क-टैकिंग बजट लेकर आई है। हालांकि सरकार का टारगेट ग्रोथ को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके लिए वह मुद्रास्फीति, यानी महंगाई बढ़ने का रिस्क लेने को तैयार है। अख्यर बिजनेस न्यूज चैनल ईटी नॉव के कंसल्टिंग एडिटर हैं। आइए 6 सवालों में देखते हैं कि ओवरऑल इस बजट को लेकर उनका क्या व्यू है।

1. क्या यह लोकलुभावन या चुनावी बजट है ?
■ अख्यर ने कहा, यह लोकलुभावन, यानी आम आदमी को खुश करने के लिए लाया गया बजट नहीं है। यह एक रिस्क लेने वाला बजट है, जिसमें निवेश करने पर जोर दिया गया है। मैंने या अन्य लोगों ने जैसी उम्मीद लगाई होगी कि यह चीजों को सस्ता करने वाला बजट होगा, यह वैसा बजट नहीं है।
■ बजट में खेती के लिए कोई खास रकब नहीं है, बल्कि ओवरऑल बेहद मामूली बढ़ावा दिया गया है।
■ टैक्स दरों में कोई खास बदलाव नहीं है, बल्कि निवेश को बढ़ाने के लिए ज्यादा टैक्स कलेक्शन पर जोर दिया गया है।

2. क्या यह महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है ?
अख्यर के मुताबिक सरकार ने निर्णय लिया है कि वह मुद्रास्फीति बढ़ाने, यानी बाजार में महंगाई तेज होने का खतरा उठाने के लिए तैयार है। बजट में फिक्स्ड

कंसल्टिडेशन, यानी राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश नहीं की गई है। सरकार इस बारे में चिंता नहीं कर रही है। इसके उलट वो निवेश पर जोर देने जा रही है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) का 35% होगा।

3. डिजिटल रुपया आएगा, लेकिन क्या यह लाभदायक होगा ?
बजट में सरकार ने अपना डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है, लेकिन अख्यर इसे लेकर अभी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। उन्होंने कहा, डिजिटल रुपया एक नया आइडिया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस तरह का होगा, इसका पैमेंट सिस्टम किस तरह का होगा, इस पर किस तरह का टैक्स लगेगा। यह सब स्पष्ट करना होगा, जो बिल्कुल एक नई बात होगी। हमें अभी इसके बारे में थोड़ा और जानना होगा।

4. ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला बजट, लेकिन यह कैसे होगा ?
अख्यर ने कहा, यह बजट ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला है। सरकार का नजरिया फॉरवर्ड लुकिंग यानी दूरदर्शी है। सरकार खुद निवेश को बढ़ावा देने की कमान संभालेगी और इसके लिए निजी सेक्टर का उपयोग करेगी। यह काम सरकार और निजी सेक्टर के जॉइंट वेवर्स के जरिए किया जाएगा। टैक्स कलेक्शन से होने वाली आय से खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, जिसमें मेन फोकस रेलवे पर रहेगा। स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटल इंडियन को बढ़ावा दिया जाएगा।

5. सरकारी एसेट के विनिवेश की बात, लेकिन ये कितना सख्तसफुल ?
अख्यर ने सरकारी एसेट के विनिवेश यानी एसेट में निजी सेक्टर को हिस्सेदारी बेचने के दावों पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, मौजूदा फाइनेंशियल इंडर में प्राइवाइजेशन की रफ्तार बेहद स्लो रही है। फेक्ट यह है कि सरकार 150 रेलवे ट्रेन, पीसंजर रूट की नीलामी कर रही थी और कोई बोली लगाने तक नहीं आया। ऐसे में इस तरीके से रेलवे जूटाने की कोशिश बड़े पैमाने पर फेल साबित हुई है, लेकिन इस फेक्टोर के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया।

6. अब पढ़कर नजर, कैसी हो सकती है नई क्रेडिट पॉलिसी ?
बजट के बाद अब सभी की नजर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर है, जिसे इसी हफ्ते अपनी क्रेडिट पॉलिसी पेश करनी है। अख्यर का मानना है कि आरबीआई की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जोखिम उठाने के फैसले का साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा, एक तरफ आरबीआई ग्रोथ में बेहद सहायक रहा है, दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है। हालांकि शक्तिशाली दास (मौजूदा आरबीआई गवर्नर) के समय में केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति से लड़ाई करने वाले आरबीआई के बजाय ग्रोथ सपोर्टिव आरबीआई रहा है।
देश में महंगाई बढ़ रही है। होलसेल प्राइस (शोक मूल्य) 14% तक बढ़ चुके हैं, जिसका मतलब है कि हम अगले 1 या 2 साल में बहुत बड़ी महंगाई के हालात में आने वाले हैं। मुद्रास्फीति पूरी दुनिया में तेज है। अमेरिका में यह नई ऊंचाई छूट रही है। फेडरल बैंक (अमेरिका) ने पहले एक साल में तीन बार ब्याज दरें बढ़ाने का अनुमान जताया था। अब लोग इसके 4 या 5 बार बढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे हालात में आरबीआई क्या करेगा?
अख्यर ने कहा, मेरे हिसाब से निर्मला सीतारमण की तरह ही आरबीआई भी रिस्क-टैकर बनेगा। दोनों कहेंगे कि हम ग्रोथ हासिल करने के लिए महंगाई बढ़ाने का जोखिम उठाएंगे। हमारा वित्तीय घाटा (fiscal deficit) करीब 6.5% है और ऐसे हालात में मुद्रा नीति बेहद सख्त होनी चाहिए। मैं नहीं सोचता कि ऐसा होने जा रहा है। आरबीआई रिस्क उठाने वाला बनेगा। यदि वे बेहद कड़ी हुई मुद्रा नीति लाने की कोशिश करते हैं, तो यह असल में महंगाई रोकने में मदद करने के बजाय इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम ही होगा।